



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-16012020-215469
CG-DL-E-16012020-215469

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]
No. 19]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSAH 24, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिसूचना

मुंबई, 1 जनवरी, 2020

सं. टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल.-महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(दिसंबर, 2019 के 26 वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी) की तरल कार्गो बर्थ में कार्यरत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 बीपीसीएल के मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण के 8 फरवरी 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा अनुमोदित किये गये थे और 06 मार्च 2017 के भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 94 में अधिसूचित हुए थे। उक्त आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गयी थी।

2.2. बीपीसीएल के अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण ने 25 फरवरी 2019; 14 जून 2019 और 10 अक्टूबर, 2019 के अपने आदेशों के द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार प्रत्येक बार 3 महीने के लिए, यानी 01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक; 01 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक और 01 अक्टूबर, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक किया गया था। 10 अक्टूबर, 2019 के आदेश में बीपीसीएल को सलाह दी गयी थी कि वह सामान्य संशोधन का अपना प्रस्ताव 30 नवम्बर, 2019 तक दायर करे।

3. इस पृष्ठभूमि में, बीपीसीएल ने 29 नवम्बर, 2019 के अपने पत्र के द्वारा अपने दरमानों के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है। बीपीसीएल का प्रस्ताव संबंधित हितधारकों के साथ परामर्शी प्रक्रिया के अधीन है।

4. इसी बीच, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बीपीसीएल के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में और नयी दरों के लागू होने में अभी कुछ और समय लगेगा, बीपीसीएल ने 18 दिसम्बर, 2019 के अपने पत्र के द्वारा इस प्राधिकरण को अनुरोध किया है कि उसके मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार और 3 महीने की अवधि के लिए, यानी 01 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक या नये दरमानों को अधिसूचना के द्वारा प्रभावी कर दिये जाने तक के समय के लिये किया जाये, क्योंकि बीपीसीएल को अपने ग्राहकों के बीजकों के लिये एस ए पी को अद्यतन करने की जरूरत पड़ेगी।

5. बीपीसीएल का प्रस्ताव संबंधित हितधारकों के साथ परामर्शी प्रक्रिया में है। बीपीसीएल से अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये बीपीसीएल के प्रस्ताव की संवीक्षा की जानी है। इस संबंध में संयुक्त सुनवाई भी की जानी है। इस प्रकार, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से विचार करने के लिये मामले को परिपक्व होने में अभी और समय लगेगा।

6.1. उप्रोक्त को देखते हुये और चूंकि बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो रही है तथा प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों को 31 दिसम्बर, 2019 से आगे विस्तार किया जाना उपयुक्त समझा जाता है।

6.2 तदनुसार, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता का और 3 महीने की अवधि के लिए, यानी 01 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक, विस्तार करता है।

6.3. यदि बीपीसीएल के निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि के लिए ग्राह्य लागत और अनुज्ञय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष को सरकार द्वारा 05 मार्च, 2019 के पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-IV) द्वारा जारी और इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित महापत्तन न्यासों में बीओटी प्रचालकों के प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 के अनुसार निपटाया जायेगा जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन- III/4/असा./410/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st January, 2020

No. TAMP/46/2016-BPCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited operating in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/46/2016-BPCL

The Bharat Petroleum Corporation Limited

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 26th day of December 2019)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating the Liquid Cargo berth at the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was approved by this Authority vide Order No. TAMP/46/2016-BPCL dated 8 February 2017 which was notified in the Gazette of India on 06 March 2017 vide Gazette No. 94. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019.

2.2. Based on the request of BPCL, the Authority vide its Orders dated 25 February 2019, 14 June 2019 and 10 October 2019 has extended the validity of the existing tariff of BPCL for a period of 3 months each i.e. from 01 April 2019 to 30 June 2019, from 01 July 2019 to 30 September 2019 & from 01 October 2019 to 31 December 2019 respectively. Vide Order dated 10 October 2019, the BPCL was advised to file its proposal for general revision of the tariff by 30 November 2019.

3. In this backdrop, the BPCL vide its letter dated 29 November 2019 has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates. The BPCL proposal is under consultation process with the relevant stakeholders.

4. In the meanwhile, considering that it may take some more time for the proposal of BPCL to be finalised and for the new rates to come into effect, BPCL has vide its letter dated 18 December 2019 requested this Authority to extend the validity of the existing Scale of Rates for a further period of 3 months i.e. from 1 January 2020 to 31 March 2020 or till such time new SOR is given by through a notification, as BPCL rates need to be updated in SAP for invoicing their customers.

5. The proposal of BPCL has been taken up on consultation with the relevant stakeholders. The proposal of BPCL is to be scrutinized to seek additional information/ clarification from BPCL. A joint hearing on the case in reference is yet to be scheduled. Thus, it may take some more time for the case to mature for final consideration of this Authority.

6.1. In view of above and since the validity of the existing tariff of BPCL will expire on 31 December 2019 and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of BPCL beyond 31 December 2019.

6.2. Accordingly, this Authority extends the validity of the existing tariff of BPCL for a further period of 3 months i.e. from 01 January 2020 to 31 March 2020 or till the date the new rates come into effect, whichever is earlier, as requested by BPCL.

6.3. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of performance of BPCL, such additional surplus will be dealt with as per Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019, for determination of tariff for BOT operators operating in Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines issued by the Government vide its letter no. PR-14019/20/2009-PG (pt-IV) dated 5 March 2019 and notified by this Authority in the Gazette of India.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./410/19]